

पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.739

वर्ष-2015 के थाना वाद सं.-5, थाना-मनशाही, जिला-कटिहार से उद्भूत।

=====

1. रहमान, पुत्र-स्वर्गीय इदरीश अली
2. नसीमा खातून, पत्नी- रहमान, दोनों गाँव के निवासी-भेरमारा, मस्जिद टोला, थाना-मनशाही, जिला-कटिहार।

.....अपीलार्थी/गण

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/प्रतिवादी/गण

=====

दोषसिद्धि की वैधता और स्थिरता-अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से प्रकट होने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए बयान में रखा जाएगा और अनुरोध किया जाएगा-पीड़ित का पति पहला व्यक्ति था जिसने पीड़ित के भाई को घटना के बारे में सूचित किया और दूरभाष से दी गई सूचना में उसने अपीलकर्ताओं के खिलाफ सीधे आरोप लगाए। हालाँकि वह विरोधी हो गये, लेकिन उसका साक्ष्य कथित स्थान पर कई चोटों को कायम रखते हुए पीड़ित की अप्राकृतिक मृत्यु को साबित करने के लिए पर्याप्त है-साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के लिए एक अपवाद गठित करता है-अपीलार्थी मुकदमे के दौरान यह दिखाने के लिए चुप रहे कि उनके अलावा कोई और कथित अपराध में शामिल था/थे, इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों के आलोक में उनके खिलाफ कथित अपराध में अपीलार्थियों की संलिप्तता का अनुमान लगाया जाता है-पीड़ित के घर और अपीलार्थी के घर में कुछ औसत है और इसके अलावा, पीड़ित के साथ उनके तनावपूर्ण संबंध थे और उसके उन्मूलन के अपीलार्थियों को पीड़ित की संपत्ति के मामले में लाभ होगा जिसे अपीलार्थी की ओर से पीड़िता की हत्या करने का सबसे विश्वसनीय कारण माना जा सकता है।

संदर्भित मामले:

i (2021) 10 एस. सी. सी. 725 (नागेंद्र शाह बनाम बिहार राज्य)

पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.739

वर्ष-2015 के थाना वाद सं.-5, थाना-मनशाही, जिला-कटिहार से उदभूत।

=====

1. रहमान, पुत्र-स्वर्गीय इदरीश अली
2. नसीमा खातून, पत्नी- रहमान, दोनों गाँव के निवासी-भेरमारा, मस्जिद टोला, थाना-मनशाही, जिला-कटिहार।

.....अपीलार्थी/गण

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/प्रतिवादी/गण

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थीगण के लिए : श्री भोला प्रसाद, अधिवक्ता

श्री संजीव कुमार सिंह, अधिवक्ता,

उत्तरदाता/गण : श्री दिलीप कुमार सिन्हा, अतिरिक्त लोक अभियोजक

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह

मौखिक निर्णय

(निर्णय: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह)

तिथि: 17-02-2024

अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री भोला प्रसाद और राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार सिन्हा को सुना।

2. वर्तमान अपील, मनशाही थाना वाद संख्या 05/2015 से उदभूत सत्र विचारण संख्या 143/2015 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, कटिहार द्वारा पारित दोषसिद्धि निर्णय दिनांकित 03.06.2017 एवं सजा का आदेश दिनांकित 09.06.2017 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा एवं जिसके तहत दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 (इसके पश्चात 'भा. दं. सं.' के रूप में संदर्भित) के तहत दंडनीय अपराध के वास्ते दोषी पाया गया है एवं तदनुसार अपीलार्थियों को दोषी ठहराया गया है एवं रु. 10,000 /- के जुर्माने के साथ आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी है एवं जुर्माने में चूक पर, उन्हें छः माह की अवधि के वास्ते आगे अतिरिक्त साधारण कारावास के वास्ते निर्देशित किया गया है।

अभियोजन की कहानीः.

3. 10.01.2015 के प्रातः काल में, सूचना देने वाले, जिसे मृतक का भाई कहा जाता है, को एक मोबाइल संचार के माध्यम से जानकारी मिली कि उसकी बहन नूरजहां खातून (जिसे इसके बाद 'पीड़ित' कहा गया है) को मार दिया गया है, उसके बाद वह घटना स्थल पर गया और अपनी बहन को मृत अवस्था में पड़ा पाया और फिर उसने पीड़ित के पति अलाउद्दीन से अपनी बहन की मौत के मामले में पूछताछ की, जिसने उसे बताया कि उसकी पत्नी, पीड़ित को पहले एक खंभे से बांध दिया गया था और उसके बाद उसके भाई रहमान और उसकी पत्नी नसीमा खातून ने उस पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मौत हो गई।

4. सूचना देने वाले ने उपरोक्त आरोपों का वर्णन करते हुए अपना *फरदबेयान* (प्रदर्श '1') दर्ज किया, जिसके आधार पर मानशाही थाना मामला संख्या 05/2015 वाली औपचारिक प्राथमिकी भा. दं. सं. की धारा 342, 343, 324, 302 और 34 के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई थी, जिसने आपराधिक कानून को गति दी।

5. जाँच पूरी होने के बाद, अपीलार्थियों के खिलाफ पुलिस द्वारा भा. दं. सं. की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था और विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 30.03.2015 के आदेश के माध्यम से उक्त अपराध का संज्ञान लिया और उसके बाद, मामले को सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य पाते हुए, इसे मुकदमे के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

6. अपीलार्थियों पर भा. दं. सं. की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था जिसे पढ़ा गया और उन्हें हिंदी में समझाया गया जिस पर उन्होंने इनकार किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

7. विचारण के दौरान, विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित गवाहों से पूछताछ की:

पीडब्लू-1:- मो. जाकिर हुसैन

पीडब्लू-2:- मो. मुस्तफा

पीडब्लू-3:- मो. अलाउद्दीन

पीडब्लू-4:- मो. अल्ताफ हुसैन

पीडब्लू-5:- डॉ. तनवीर हैदर (पोस्टमॉर्टम जांच के पर्यवेक्षक)

पीडब्लू-6:- मो. सनाउल्लाह (मृतक का साला)

पीडब्लू-7:- बिनोद कुमार सिंह (जांच अधिकारी)

पीडब्लू-8:- डॉ. सुशील कुमार गुप्ता (मृतक के शरीर का पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर)

8. दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजों को साबित किया और उन्हें निम्नानुसार प्रदर्शित किया:

प्रदर्श-1:- *फरदबेयान* पर एक गवाह के हस्ताक्षर

प्रदर्श-1/1:- एक मो.सनाउल्लाह का *फरदबेयान* पर हस्ताक्षर

प्रदर्श-2:- मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

प्रदर्श-2/1:- पोस्टमॉर्टम प्रतिवेदन पर गवाह के हस्ताक्षर

प्रदर्श-3:- एस. आई. बी. के. सिंह द्वारा *फरदबेयान*

प्रदर्श.-4:- औपचारिक एफ. आई. आर.

प्रदर्श.-5:- फरदबेयान पर एक समर्थन,

प्रदर्श.-6:- आरोपी रहमान की गिरफ्तारी का ज्ञापन

प्रदर्श.-7:- अभियुक्त नसीमा खातून की गिरफ्तारी का ज्ञापन

प्रदर्श.-8:- पूछताछ रिपोर्ट की कार्बन प्रति

प्रदर्श.-9:- विसरा के लिए अग्रेषित पत्र

प्रदर्श.-10:- हिस्टोपैथोलॉजिकल परीक्षण के लिए अग्रेषित पत्र

9. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के पूरा होने के बाद, निचली अदालत ने अपीलार्थियों के बयान दर्ज किए जिसमें अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से उनके खिलाफ पेश होने वाली मुख्य अभिशंसी परिस्थिति को उन्हें समझाया गया था जिसे अपीलार्थियों द्वारा इनकार कर दिया गया था। उन्होंने खुद को निर्दोष होने का दावा किया लेकिन दं. प्र. सं. की धारा 313 के तहत उनके बयान दर्ज करते समय बचाव का कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया।

10. अपीलकर्ताओं ने अपने बचाव में मजारुल हक नामक एक गवाह को पेश किया और उससे पूछताछ की।

11. अपीलार्थियों को दोषी ठहराते समय विद्वत विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से पीडब्लू-3, पीडब्लू-4, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-8 की गवाही पर भरोसा किया और गैर-सरकारी गवाहों पीडब्लू-4, पीडब्लू-6 द्वारा दिए गए साक्ष्य को विश्वसनीय माना और मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दिए गए चिकित्सा निष्कर्षों को भी अभियोजन पक्ष के आरोप के पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में ध्यान में रखा।

अपीलार्थियों की ओर से दिए गए तर्क:

12. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील श्री भोला प्रसाद समर्पित करते हैं कि तत्काल मामले में हत्या की कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, हालांकि, पीडब्लू-3 को एक चश्मदीद गवाह कहा जाता है, लेकिन निचली अदालत के समक्ष

उन्होंने कथित अपराध में अपीलार्थियों की संलिप्तता का सुझाव देने वाला कोई सबूत नहीं दिया और उन्होंने पीड़ित की हत्या में शामिल दोषियों के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया। यह आगे समर्पित किया जाता है कि सूचना देने वाला एक चश्मदीद गवाह नहीं है और उसने मुख्य रूप से अभियोजन साक्षी 3 से, जिसे शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था, मोबाइल फ़ोन पर प्राप्त संचार के आधार पर अपने *फर्दबयान* में आरोप लगाए इसलिए अभियोजन पक्ष के आरोपों की नींव अप्रमाणित रही। मुखबिर द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार, अपीलार्थियों द्वारा पीड़ित पर बेरहमी से हमला किया गया था, लेकिन पोस्टमॉर्टम जांच करने वाले डॉक्टर, पीडब्लू-8 ने कहा कि पीड़ित की मौत का कारण बंधन द्वारा गला घोटने के परिणामस्वरूप *दम घुटना* है जो पूरी तरह से हमले के आरोप के खिलाफ है। विद्वत विचारण न्यायालय ने पीडब्लू-6 के साक्ष्य पर भरोसा किया, जबकि वह आरोप पत्र का गवाह नहीं था, वास्तव में मृतक ने आत्महत्या कर ली, जिसे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी गर्दन पर पाए गए बंधन के निशान से समर्थन मिलता है। यह आगे समर्पित किया जाता है कि पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 को स्वतंत्रत गवाह कहा जाता है, लेकिन वे मुकर गए और उनके साक्ष्य अभियोजन पक्ष की मदद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी विद्वत विचारण न्यायालय ने उन पर भरोसा किया। विद्वान वकील आगे समर्पित करते हैं कि दोनों अपीलार्थी बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं और उन्होंने लगभग सात साल जेल में बिताए हैं।

राज्य की ओर से दिए गए तर्क:

13. श्री दिलीप कुमार सिन्हा, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान एपीपी ने समर्पित किया कि तत्काल मामला क्रूर हत्या से संबंधित है जो अपीलार्थियों द्वारा संपत्ति विवाद के कारण की गई थी क्योंकि पीड़ित का पति एक अंधा व्यक्ति है और पीड़ित के पति की संपत्ति हड़पने के वास्ते, अपीलकर्ताओं ने पहले पीड़ित को अपने घर के अंदर एक खंभे से बांध दिया और फिर उस पर बुरी तरह से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई और इस संबंध में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में वर्णित पीड़ित के शरीर पर पाई गई

बाहरी चोटें बहुत प्रासंगिक हैं और निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष आरोपित अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं के अपराध को साबित करने में सफल रहा।

14. सबसे पहले हम अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य पर चर्चा करना चाहेंगे।

15. पीडब्लू-1, मो. जाकिर हुसैन, जिसे पीड़ित के साथ अपीलकर्ताओं द्वारा कथित रूप से किए गए हमले की घटना का चश्मदीद गवाह कहा जाता है, शत्रुतापूर्ण हो गया और घटना के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया और यहां तक कि पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करना भी याद नहीं किया।

16. पीडब्लू-2, मो. मुस्तफा, जिसे अपीलार्थियों का सह-ग्रामीण कहा जाता है, ने बयान दिया कि पीड़ित नूरजहां खातून की मृत्यु हो गई थी, उसने पीड़ित को अपने पति के घर में मृत अवस्था में पड़ा देखा और अपीलार्थी रहमान पीड़ित के पति का अपना भाई है। उन्होंने आगे कहा कि उस घटना के संबंध में एक *पंचायत* की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें उन्होंने एक *पंच* के रूप में भी भाग लिया था। हालाँकि, इस गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था, लेकिन उसका सबूत यह दिखाने के लिए प्रासंगिक है कि पीड़ित की मृत्यु एक अप्राकृतिक मृत्यु थी।

17. पीडब्लू-3, मो. अलाउद्दीन अभियोजन पक्ष का एक महत्वपूर्ण गवाह है क्योंकि अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार वह पहला व्यक्ति था जिसने पीड़ित के भाई जिसने प्राथमिकी दर्ज की, को कथित घटना के बारे में सूचित किया। हालाँकि, इस गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था, लेकिन उसने पीड़ित की अप्राकृतिक मृत्यु के तथ्य को साबित कर दिया, जो उसकी पत्नी थी और इस संबंध में उसका साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पक्ष में जाता है।

18. पीडब्लू-4, मुखबिर ने बयान दिया कि उसके द्वारा सुबह 6 बजे, 10.01.2015 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी, पीड़ित के पति, अलाउद्दीन ने उसे मोबाइल

संचार के माध्यम से सूचित किया कि उसकी बहन यानी पीड़ित पर बेरहमी से हमला किया गया था और फिर उसने (पीडब्लू-4) अपने बहनोई सनाउल्लाह को पीड़ित के घर जाने के लिए कहा और उसे बताया कि वह भी आ रहा है और जब वह वहाँ पहुँचा, तो उसने अपनी बहन को उसके ससुराल में मृत पड़ा देखा और उसके बाद, उसने पीड़ित के पति से मामले की पूछताछ की, जिसने उसे बताया कि अपीलकर्ताओं ने पहले पीड़ित को एक खंभे से बांध दिया और उसके बाद उसके साथ हमला करना शुरू कर दिया और उसने पीड़ित की गर्दन पर कुछ काला धब्बा देखा। इस गवाह ने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं ने पीड़ित की संपत्ति हड़पने के लिए उसकी हत्या कर दी। उन्होंने जिरह में आगे कहा कि पीड़ित के पति और अपीलार्थी (रहमान) के बीच भूमि विवाद पिछले पांच वर्षों से चल रहा था। इस गवाह के साक्ष्य से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि पीड़ित अपने पति के घर में मृत अवस्था में पड़ी पाई गई थी और उसके शरीर पर कई चोटें थीं और पीड़ित के पति और अपीलार्थियों के बीच संपत्ति विवाद था और उक्त विवाद को घटना की उत्पत्ति माना जा सकता है।

19. कहा जाता है कि पीडब्लू-5 सदर अस्पताल, कटिहार में डॉ. एस. के. गुप्ता (पीडब्लू-8) द्वारा किए गए पोस्टमॉर्टम परीक्षण के समय मौजूद था और वह पोस्टमॉर्टम परीक्षण के समय एक पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद था।

20. पीडब्लू-6, मो. सनाउल्ला अभियोजन पक्ष का प्रमुख गवाह है क्योंकि उसे कथित घटना का चश्मदीद गवाह कहा जाता है और वह मुखबिर का बहनोई है। उन्होंने गवाही दी कि 09.01.2015 को, वह पीड़ित के घर गया और उस समय, उसने पीड़ित को खाना पकाते हुए पाया और फिर उसे पीड़ित द्वारा अवगत कराया गया कि एक बीघा जमीन का एक टुकड़ा पीड़ित द्वारा अनुबंध खेती पर दिया गया था, इस कारण से, अपीलार्थी रहमान और पीड़ित के बीच विवाद पैदा हो गया। गवाह ने आगे कहा कि जब वह पीड़िता के घर गया तो अपीलकर्ता वहाँ आए और पीड़िता को एक खंभे से बांध दिया और उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, फिर उसने उन्हें रोकने की कोशिश की और उन्हें *पंचायत*

की बैठक करने के लिए कहा और उसके बाद आरोपी भाग गया और उसके बाद वह अपने ग्राम लौट आया। गवाह ने अपने प्रति-परीक्षण में कहा कि उसका घर पीड़ित के घर से लगभग चार किलोमीटर दूर स्थित है और उसने उसके सामने हुई घटना के संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया और न ही अपने बहनोई (मुखबिर) को उक्त घटना के बारे में सूचित किया। इस गवाह के साक्ष्य से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पीड़ित द्वारा दी गई *बीघा* भूमि की संविदात्मक खेती के कारण पीड़ित और अपीलार्थियों के बीच कुछ तनाव था।

21. तत्काल मामले में जांच अधिकारी, जिनसे पीडब्लू-7 के रूप में पूछताछ की गई थी, का साक्ष्य विशेष रूप से घटना स्थल के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुख्य प्रति-परिक्षण की कंडिका '8' में कहा कि उसने घटना स्थल का निरीक्षण किया और पाया कि घटना स्थल अपीलार्थियों और पीड़ित के पति के घर का *बरामदा (पोर्टिको)* था, इस कथन से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलार्थियों और पीड़ित के पति का एक ही *बरामदा पोर्टिको* है।

22. पीडब्लू-8, डॉ. सुशील कुमार गुप्ता ने मृतक के शरीर का पोस्टमॉर्टम किया। उन्हें मृतक के शरीर पर निम्नलिखित बाहरी चोटें मिलीं:

(i) गर्दन के ऊपरी भाग पर क्षैतिज रूप से चलने वाले 2 मिमी आकार के रंग में लाल-काले रंग का अच्छी तरह से परिभाषित रैखिक बंधन चिह्न बाएँ जबड़ा कोण के पीछे के स्तर से दाएँ जबड़ा कोण के पीछे के स्तर तक।

(ii) कलाई के जोड़ के ठीक ऊपर दाहिने अग्र-भुजा पर एक घर्षण, आकार में 2 सेमी केवल अग्र-भुजा को पूरी तरह से घेरता है।

(iii) अग्र-भुजा की दाहिनी ओर की हड्डी का टूटना।

(iv) कलाई के जोड़ के ठीक ऊपर बाईं अग्र-भुजा पर एक घर्षण जो अग्र-भुजा को 2 सेमी आकार में घेरता है।

(v) बाहरी जननांग।

पीडब्लू-8 ने गला घोटने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध के कारण मृतक की मृत्यु का कारण बताया। गवाह ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को साबित किया जिसे प्रदर्श.-2 के रूप में चिह्नित किया गया था।

23. अपीलकर्ताओं ने अपने बचाव में मज़ारुल हक नाम के एक गवाह को पेश किया, जिससे डी. डब्ल्यू.-1 के रूप में पूछताछ की गई। उसने अपदस्थ कर दिया कि वह अपीलकर्ताओं, पीड़ित और पीड़ित के पति को जानता था जो अंधा है। उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता कुछ अस्वस्थ थी और वह पीड़िता के घर गया और उसका शव देखा लेकिन उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला। उक्त कथन पीडब्लू-8 द्वारा दिए गए साक्ष्य के पूरी तरह से विरोधाभासी है क्योंकि मृतक के शरीर पर कई चोटें पाई गई थीं जिन पर अपीलकर्ताओं द्वारा विवाद नहीं किया गया था।

विश्लेषण:

24. दोनों पक्षों को सुना और निचली अदालत के मामले के रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया और अपीलार्थियों के बयानों का भी अध्ययन किया।

25. पीडब्लू-8 द्वारा दिए गए चिकित्सा साक्ष्य कई चोटों को बनाए रखते हुए पीड़ित की अप्राकृतिक मृत्यु को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। पीड़ित के शरीर पर कुल पांच बाहरी चोटें पाई गईं, जिससे पता चलता है कि उस पर बेरहमी से हमला किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे कई चोटें आईं। प्राथमिकी में लगाए गए आरोप के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने पहले पीड़िता को एक खंभे से बांध दिया और उसके बाद उस पर बुरी तरह से हमला किया। विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को कथित घटना के लिए दोषी ठहराया और परिणामस्वरूप उन्हें भा.दं.सं. की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया। अब, इस न्यायालय को अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की वैधता और स्थिरता का निर्णय करना है और यह पता लगाना है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वास को प्रेरित करते हैं और उन कथित अपराधों के लिए

अपीलार्थियों की दोषसिद्धि जिनके लिए उन पर आरोप लगाए गए थे, को उचित ठहराने के वास्ते प्रयास हैं।

26. पीडब्लू-4 और पीडब्लू-6 के साक्ष्य के अनुसार, भूमि विवाद के कारण पीड़ित और अपीलार्थियों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे और उक्त तनावपूर्ण संबंध का खंडन करने के लिए, अपीलार्थियों द्वारा डीडब्ल्यू-1 की जांच के अलावा कोई सबूत नहीं लाया गया था, जो विश्वसनीय नहीं लगता क्योंकि उसने जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मृतक के शरीर पर चोट के निशान की उपस्थिति के बारे में विरोधाभासी बयान दिया। अपीलार्थी पी. डब्ल्यू.-4 और पी. डब्ल्यू.-6 की प्रतिपरीक्षा से अपीलार्थी और पीड़ित के बीच के प्रतिकूल शब्द का खंडन करने के लिए कोई तथ्य प्राप्त करने में सफल नहीं हुए।

27. मान लीजिए, पीड़ित का पति जन्म से अंधा है और पीड़ित वह व्यक्ति था जो बाहरी मामलों सहित उसके घर के सभी मामलों को नियंत्रित और प्रबंधित करता था, इसलिए कोई भी उसे समाप्त करके आसानी से उसकी संपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है।

28. वर्तमान मामले में पीडब्लू-6 अभियोजन पक्ष का एक सितारा गवाह है क्योंकि वह पीड़ित की मृत्यु से ठीक एक दिन पहले 09.01.2015 को पीड़ित के घर गया था। उसने अपदस्थ किया कि जब वह उसके घर गया तो पीड़ित भोजन तैयार कर रही थी और उसने खुलासा किया कि उसने उसे अनुबंध खेती पर एक *बीघा* जमीन दी थी जिससे उसके और अपीलार्थियों के बीच विवाद हो गया था। उन्होंने आगे कहा कि जब वह पीड़िता के घर पर मौजूद थे तो अचानक अपीलकर्ता वहां आए और पीड़िता को जबरन एक खंभे से बांध दिया और उसके बाद उस पर हमला करना शुरू कर दिया, उसने उन्हें रोकने की कोशिश की और उन्हें *पंचायत* की बैठक करने के लिए राजी किया, लेकिन उसके बाद अपीलकर्ता भाग गए। उन्होंने आगे कहा कि उक्त घटना की सूचना उन्होंने अपने ग्राम में दी थी और अगले दिन उन्हें टेलीफोन पर जानकारी मिली कि पीड़ित की मृत्यु हो गई है।

यद्यपि इस गवाह द्वारा जिरह में दिए गए, कथनानुसार उसने 09.01.2015 को घटित घटना का खुलासा, सूचनादाता को नहीं किया, जो इस गवाह का साला है, लेकिन केवल इस तथ्य से इस गवाह के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है क्योंकि घटना की जानकारी उसने अपने ग्राम में दी थी। जिरह में इस गवाह द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, इस गवाह का घर पीड़ित के घर से सिर्फ चार किलोमीटर दूर स्थित है। इसलिए अपीलार्थी और पीड़ित के बीच कुछ तनावपूर्ण माहौल सुनकर पीड़ित के घर जाना उसके लिए बहुत स्वाभाविक था। विद्वत विचारण न्यायालय ने इस गवाह के साक्ष्य पर उचित रूप से भरोसा रखा।

29. प्राथमिकी के अनुसार, पीड़ित का पति पहला व्यक्ति था जिसने पीड़ित के भाई को घटना के बारे में सूचित किया और टेलीफोन पर दी गई जानकारी में उसने अपीलार्थियों के खिलाफ सीधे आरोप लगाए। हालाँकि वह शत्रुतापूर्ण था, लेकिन उसके सबूत कथित स्थान पर कई चोटों को बनाए रखते हुए पीड़ित की अप्राकृतिक मौत को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं।

30. जाँच अधिकारी (पीडब्लू-7) के साक्ष्य के अनुसार, क्रूर *मारपिट* की कथित घटना अपीलार्थियों के घर के *बरामदे* (पोर्च) में हुई और इस संबंध में पीडब्लू-7 का उनके द्वारा उनके मुख्य प्रति-परीक्षण की कंडिका-8 में दिया बयान प्रासंगिक है।

पीड़ित का पति जन्म से अंधा है और उसके और उसकी पत्नी (पीड़ित) के बीच कोई विवाद दिखाने के लिए कोई सामग्री या सबूत नहीं है, इसलिए उसके पास दूसरों की मदद से अपनी पत्नी पर हमला करवाने का कोई कारण नहीं था। अपीलार्थियों के पास पीड़ित पर हमला करने का पर्याप्त अवसर था क्योंकि जांच अधिकारी के साक्ष्य के अनुसार, पीड़ित के घर और अपीलार्थियों के घर में एक ही बरामदा है और इसके अलावा, पीड़ित के साथ उनके तनावपूर्ण संबंध थे और उसके उन्मूलन के बाद, उन्हें पीड़ित की संपत्ति के मामले में लाभ

होगा, जिसे पीड़ित की हत्या करने के लिए उनकी ओर से सबसे विश्वसनीय कारण माना जा सकता है।

31. यदि पीड़ित पर अपीलार्थियों के अलावा किसी और ने हमला किया था तो ऐसी घटना और दोषियों का विवरण अपीलार्थियों की जानकारी में आया होगा। लेकिन इस संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा कोई बचाव नहीं किया गया था और न ही उनके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज करते समय अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से उनके खिलाफ दिखाई देने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों की व्याख्या करने के लिए कोई बयान दिया गया था।

32. **नागेंद्र शाह बनाम बिहार राज्य (2021) 10 एस सी सी 725** में प्रतिवेदन मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि *"साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के लिए एक अपवाद है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 उन वादों पर लागू होगी जहां अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को स्थापित करने में सफल रहा है जिनसे कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है जो अभियुक्त की विशेष जानकारी में हैं। जब अभियुक्त उक्त अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो न्यायालय हमेशा एक उचित निष्कर्ष निकाल सकता है।"*

33. तत्काल मामले में, उपरोक्त चर्चा किए गए साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के घर के बरामदे में पीड़ित पर किए गए क्रूर हमले और संपत्ति विवाद के कारण पीड़ित और अपीलार्थियों के बीच तनावपूर्ण संबंध स्थापित करने में सफल रहा। यदि पीड़ित पर किसी और द्वारा हमला किया गया था, तो अपीलकर्ताओं ने ऐसे उपद्रवियों के विवरण का खुलासा किया होगा क्योंकि यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपीलकर्ताओं के घर के बरामदे में उनकी जानकारी के बिना पीड़ित पर हमला किया था।

34. अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से अपीलार्थियों के खिलाफ उपस्थित होने वाली उपरोक्त चर्चा की गई परिस्थितियों के आलोक में, यह न्यायालय यह राय बनाता है कि अपीलार्थियों के पीड़ित के साथ तनावपूर्ण संबंध थे और पीड़ित की मृत्यु के बाद उन्हें सबसे अधिक लाभ होगा क्योंकि पीड़ित का पति अंधा है और संपत्ति के मामलों सहित उसके घर के सभी मामलों का प्रबंधन करने के लिए पीड़ित के अलावा कोई नहीं था और यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि अपीलार्थियों के अलावा किसी अन्य ने अपीलार्थियों की जानकारी के बिना पीड़ित पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी क्योंकि घटना स्थल को जाँचकर्ता के साक्ष्य के अनुसार अपीलार्थियों के घर का बरामदा कहा जाता है, जिन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अपीलार्थी मुकदमे के दौरान यह दिखाने के लिए चुप रहे कि उनके अलावा कोई और कथित अपराध में शामिल था/थे, इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों के आलोक में उनके खिलाफ कथित अपराध में अपीलार्थियों की संलिप्तता का अनुमान लगाया जाता है। विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को उन कथित अपराधों के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया जिनके लिए उन पर आरोप लगाया गया था और निर्णय और आदेश में कोई दुर्बलता और अवैधता नहीं है, इस न्यायालय को इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है, इसलिए यह खारिज हो जाता है।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

मायनाज़/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।